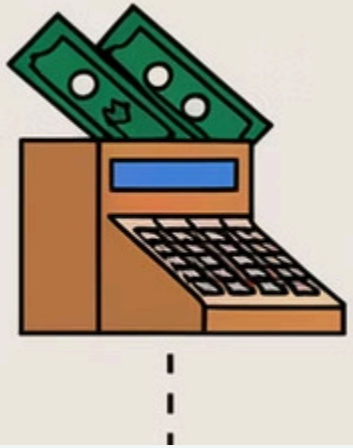

आज के भारतीय शिक्षा को परेशान करने वाले '3Cs'

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के परिचय में एक ऐसी सरकार छिपी है जो भारत के बच्चों और युवाओं की शिक्षा के प्रति उदासीन प्रतीत होती है। पिछले दशक में, केंद्र सरकार ने यह प्रदर्शित किया है कि उसकी शैक्षिक प्राथमिकताएं तीन मुख्य एजेंडा आइटम - शक्ति का केंद्रीकरण, शिक्षा का वाणिज्यीकरण और पाठ्यक्रम और संस्थानों का सांप्रदायिकरण - के घूमते हैं।

ये तीन बिंदु भारत के शिक्षा परिदृश्य को व्यवस्थित रूप से पुनर्गठित कर रहे हैं, जिसके दूरगामी परिणाम छात्रों, शिक्षकों और राष्ट्र के भविष्य के लिए हैं। आइए देखें कि ये '3Cs' भारत के शैक्षिक ढांचे को मूलभूत रूप से कैसे बदल रहे हैं।

केंद्रीकरण: संघीय शिक्षा संरचना को कमजोर करना

1

केंद्रीय सलाहकार बोर्ड निष्क्रिय

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सितंबर 2019 के बाद से कोई बैठक नहीं की है, बावजूद NEP 2020 को लागू करने के।

2

राज्य परामर्श नजरअंदाज किया गया

केंद्र सरकार ने NEP नीतियों के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया है।

3

संवैधानिक उल्लंघन

शिक्षा सहयोगी सूची में है लेकिन केंद्र सरकार के एकमात्र क्षेत्र के रूप में माना जा रहा है।

अनियंत्रित केंद्रीकरण इस सरकार के कार्यकलाप का प्रमुख लक्षण रहा है, जिसके सबसे विनाशकारी परिणाम शिक्षा में देखे जा रहे हैं। यह दृष्टिकोण संवैधानिक ढांचे के विपरीत है, जो शिक्षा को सहयोगी सूची में रखता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है।

शिक्षा प्रशासन में ब्रह्मास्त्र प्रवृत्ति

एसएसए धन रोकना

राज्य सरकारों को पीएम-श्री योजना लागू करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत देय अनुदान रोक दिए गए हैं।

आरटीई कार्यान्वयन प्रभावित

शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए राज्यों को वर्षों से धन देय है।

संसदीय समिति हस्तक्षेप

द्विदलीय संसदीय स्थायी समिति ने राज्य सरकारों को एसएसए धन अनिर्बंध रूप से जारी करने का आह्वान किया है।

संवाद की कमी के साथ-साथ शिक्षा प्रशासन में केवल 'ब्रह्मास्त्र प्रवृत्ति' कहा जा सकता है। ये कार्रवाइयां एक ऐसी सरकार को दर्शाती हैं जो प्रचार और प्रदर्शन में अधिक रुचि रखती है, न कि संवैधानिक रूप से गारंटीकृत शिक्षा के अधिकार को बनाए रखने में।

🎉 Eid Al-Fitr Special Offer! 🎉

Ojank IAS लेकर आया है बंपर डिस्काउंट अपने खास बैचों पर! 📚🔥

✅ Shakti Test Series – सिर्फ ₹1,799 ✅ Brahmastra Batch – सिर्फ ₹19,999 ✅ Combo Batch – सिर्फ ₹39,999 ✅ CSAT Batch – सिर्फ ₹4,000

अभी कॉल करें 📞 875071100/22/33/44/55

Or fill the form:-
https://docs.google.com/forms/d/1PzN1wR9JewyqDUCQY4kP60HuoefjYTVnmIL69PIRmxc/edit

उच्च शिक्षा: उपकुलपति नियुक्तियों का केंद्रीकरण

यूजीसी दिशानिर्देश 2025

कठोर मसौदा दिशानिर्देश राज्य सरकारों को उपकुलपति नियुक्तियों से बाहर करते हैं

प्रभावित राज्य विश्वविद्यालय

राज्यों द्वारा स्थापित, वित्त पोषित और संचालित विश्वविद्यालयों को भी स्वायत्तता खो देते हैं

राज्यपाल के अधिकार

केंद्र सरकार को राज्यपालों के माध्यम से शक्ति प्राप्त होती है, जो आमतौर पर कुलाधिपति के रूप में नामित होते हैं

संघवाद का खतरा

इसका मतलब संघीय सूची के विषय को केंद्रीय संरक्षण में बदलने का पिछला दरवाजा है

उच्च शिक्षा में, केंद्रीकरण एजेंडा 2025 के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मसौदा दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रकट हुआ है। यह कदम राज्य विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों के चयन में केंद्र सरकार को लगभग एकाधिकार शक्ति देता है, जो समकालीन भारत में शैक्षिक संघवाद के सबसे गंभीर खतरों में से एक है।

वाणिज्यीकरण: सार्वजनिक शिक्षा का पलायन

89,441

बंद हुए सार्वजनिक स्कूल

2014 से बंद या एकीकृत हुए स्कूल

42,944

जोड़े गए निजी स्कूल

इसी अवधि में स्थापित अतिरिक्त निजी संस्थान

100%

HEFA ऋण चुकाना

छात्र शुल्क के माध्यम से 100% तक ऋण चुकाया जा रहा है

मोदी सरकार की शिक्षा का वाणिज्यीकरण एनईपी के अनुरूप खुले तौर पर हो रहा है। पड़ोसी स्कूलों की अवधारणा को स्कूल परिसरों को लाकर पलट दिया गया है, जिसका अर्थ है सार्वजनिक शिक्षा का व्यापक स्तर पर बंद होना और स्कूली शिक्षा का अनियंत्रित निजीकरण।

उच्च शिक्षा में अनुदानों से ऋणों में बदलाव

उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी (HEFA) का परिचय

उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी यूजीसी के ब्लॉक-अनुदान प्रणाली को प्रतिस्थापित करती है

शुल्क वृद्धि

छात्रों को बढ़ते शैक्षिक शुल्कों के माध्यम से वित्तीय बोझ वहन करना पड़ता है

बाजार दर ऋण

विश्वविद्यालयों को वाणिज्यिक ब्याज दरों पर ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है

राजस्व चुकौती

संस्थानों को अपने स्वयं के राजस्व से चुकौती करने के लिए बाध्य किया जाता है

उच्च शिक्षा में, अनुदानों से ऋणों में बदलाव ने संस्थानों के वित्तपोषण के तरीके को मूलभूत रूप से बदल दिया है। शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 364वीं रिपोर्ट के अनुसार, HEFA ऋणों का 78% से 100% तक विश्वविद्यालयों द्वारा छात्र शुल्कों से चुकाया जा रहा है, जिससे वित्तीय बोझ प्रभावी रूप से छात्रों पर स्थानांतरित हो जाता है।

भ्रष्टाचार: वाणिज्यीकरण का एक उपोत्पाद

एनएएसी रिश्वतखोरी घोटाला

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद में भ्रष्टाचार मामलों में शामिल

एनटीए विवाद

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी वित्तीय कुप्रबंधन और अक्षमता के लिए जांच के घेरे में

व्यापक भ्रष्टाचार

सरकार द्वारा प्रायोजित राजनीतिकरण से जुड़ा सार्वजनिक शिक्षा में बढ़ता सीनिकता

भारत के शिक्षा प्रणालियों में भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्ति इस वाणिज्यीकरण का एक प्रकटन है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद में रिश्वतखोरी घोटाले से लेकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की दुर्भाग्यपूर्ण अक्षमता तक, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालियां और एजेंसियां वित्तीय कुप्रबंधन के लिए लगातार सुर्खियों में हैं।

CURRENT AFFAIRS "SURE" HWC Method by OJAANK SIR (2nd MONTH) ⏳

📲 **Exclusively on the OJAANK APP**

👉 **Download Ojaank App Now Link :-** https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ojaank
👉 **Course Link -** https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/524

तैयारी में No.1 बनने का ये है Golden Chance 🌟

Ojaank IAS में Admission लेने लिए दिए गए link पर Click करके Form भरें -
https://docs.google.com/forms/d/1PzN1wR9JewyqDUCQY4kP60HuoefjYTVnmIL69PIRmxc/edit

अधिक जानकारी के लिए तुरंत Call करें :- 8750711100/22/33/44/55

👉 **Ojaank Sir के साथ सीधा Whatsapp से जुड़ें : 8285894079**

समुदायीकरण: इतिहास और पाठ्यक्रम का पुनर्लेखन

एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक संशोधन

पाठ्यपुस्तकों को भारतीय इतिहास को स्वच्छ करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं और अवधियों को किसी विशिष्ट विचारधारात्मक कथा के अनुरूप हटा दिया गया है या संशोधित कर दिया गया है।

- महात्मा गांधी की हत्या पाठ्यक्रम से हटा दी गई
- मुगल भारत पर अनुच्छेद हटा दिए गए
- भारतीय संविधान के प्रस्तावना को प्रारंभ में हटा दिया गया था

विचारधारात्मक नियुक्तियां

शैक्षिक संस्थानों में नेतृत्व और संकाय संरचना में व्यवस्थित परिवर्तन देखे गए हैं, जहां शैक्षिक योग्यता के बजाय शासन की विचारधारा के साथ संरेखित लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

- गुणवत्ता चिंताओं के बावजूद शासन-अनुकूल प्रोफेसरों को नियुक्त किया गया
- प्रमुख संस्थानों में नेतृत्व पदों को "अनुकूल विचारधारावादियों" से भरा गया
- प्रोफेसरशिप के लिए योग्यता आवश्यकताओं को कमजोर किया जा रहा है

आधुनिक भारत के मंदिरों पर हमला

आईआईटी पर दबाव

नेहरू द्वारा "आधुनिक भारत के मंदिर" के रूप में वर्णित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सरकार की विचारधारा से संरेखित नेतृत्व पदों के लिए बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं।

आईआईएम में बदलाव

प्रमुख प्रबंधन संस्थान भी समान दबाव का सामना कर रहे हैं क्योंकि नियुक्तियों और पाठ्यक्रम में विचारधारात्मक विचारों द्वारा शैक्षिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

शैक्षिक गुणवत्ता चिंताएं

यूजीसी का प्रयास प्रोफेसरशिप और उपकुलपति पदों के लिए योग्यताओं को कम करना, शैक्षिक उत्कृष्टता के बजाय विचारधारात्मक विचारों से प्रेरित शिक्षाविदों के प्रवाह को सक्षम करने के लिए प्रतीत होता है।

छात्रों पर प्रभाव: भार सहना

कम पहुंच

कम सार्वजनिक स्कूल और उच्च शुल्क शैक्षिक अवसरों को सीमित करते हैं

गुणवत्ता में कमी

विचारधारात्मक नियुक्तियों से शिक्षण मानकों पर असर पड़ता है

वित्तीय बोझ

छात्र संस्थानों द्वारा व्यय को आगे बढ़ाने के कारण लागत में वृद्धि का सामना करते हैं

सीमित भविष्य के अवसर

शैक्षिक असमानता सामाजिक-आर्थिक विभाजन को बढ़ाती है

केंद्रीकरण, वाणिज्यीकरण और सांप्रदायिकरण के इस एकतरफा दबाव के परिणामस्वरूप भारत के छात्रों पर सीधा असर पड़ा है। गरीबों को सार्वजनिक शिक्षा से बाहर कर दिया गया है और महंगे निजी स्कूलों में धकेल दिया गया है। उच्च शिक्षा के छात्र ऋण चुकाने में संघर्ष करते हुए बढ़ते शुल्क का सामना करते हैं, जबकि सभी छात्र एक लगातार विचारधारात्मक पाठ्यक्रम का सामना करते हैं।

आगे का रास्ता: सार्वजनिक शिक्षा को पुनः प्राप्त करना

1

संवैधानिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करना

शैक्षिक प्रशासन में संघीय संरचना में वापसी करना

सार्वजनिक शिक्षा में पुनर्निवेश करना

निजीकरण की प्रवृत्ति को उलटना और सार्वजनिक संस्थानों को मजबूत करना

शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा करना

पाठ्यक्रम और नियुक्तियों को योग्यता पर आधारित बनाना, न कि विचारधारा पर

पिछले दशक में, भारत की शिक्षा प्रणालियों को सार्वजनिक सेवा की भावना से व्यवस्थित रूप से साफ कर दिया गया है, और शिक्षा नीति को पहुंच और गुणवत्ता के बारे में चिंताओं से मुक्त कर दिया गया है। भारत की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली का यह नरसंहार समाप्त होना चाहिए। आगे का रास्ता संवैधानिक मूल्यों के प्रति पुनर्प्रतिबद्धता, सार्वजनिक शिक्षा में महत्वपूर्ण पुनर्निवेश, और विचारधारा के हस्तक्षेप से शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा की मांग करता है।

👉 ऐसी ही UPSC Special Current News PDF के लिए Visit करें हमारी Official Website : www.ojaank.com

👉 DAILY FREE ENGLISH NEWS PDFs Link :
https://www.ojaank.com/books/current-affairs-magazine

👉 DAILY FREE ENGLISH NEWS PDFs Link : https://www.ojaank.com/hindi/books/current-affairs-magazine